Received: Mar '23
Revised:
Accepted: Apr '23

© 2023 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

INDO-MYANMAR RELATIONS IN THE 21ST CENTURY: A STUDY
21वीं सदी में भारत–म्यांमार संबंध : एक अध्ययन

Dr. Ajit
Assistant Professor, Department of Political Science, Govt. Kamla Modi Girls College, Neemkathana
E-mail: ajitsharma037@gmail.com

ABSTRACT

The relationship between India and Myanmar is centuries old, and Buddhism is the strong thread in these relationships. The two countries signed a friendship treaty in 1951. Geopolitically, Myanmar is important for India, as it stands at the crossroads of India-Southeast Asia relations. Myanmar's role is also important in curbing the growing militancy in Northeast India and counterbalancing China's growing influence in Myanmar. Cooperation between the two countries is also becoming visible in various fields, as India was one of Myanmar's main trading partners in the last financial year. India exported $820 million to Myanmar and imported $540 million. Both countries are also cooperating with each other in investment, energy security, food security, etc. India has also provided special assistance to Myanmar in the construction and operation of various projects there. But there are also some challenges in the relations between the two nations, such as the Rohingya problem, the increasing influence of China in Myanmar, increasing drug trafficking from Myanmar in the eastern states, etc. However, by solving the Rohingya problem, improving projects, and enhancing cooperation in much-anticipated forums, bilateral relations can be strengthened.

भारत और म्यांमार के संबंध सदियों पुराने है और बौद्ध धर्म इन रिश्तों की मजबूत डोर है। दोनों देशों ने 1951 में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। भू–राजनीतिक दृष्टि से म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भौगोलिक रूप से भारत –दक्षिणपूर्व संबंधों के चौराहे पर खड़ा है। पूर्वोत्तर भारत में बढ़ते उग्रवाद पर लगाम लगाने तथा म्यांमार में बढ़ते चीन के प्रभाव को प्रति संतुलित करने में भी म्यांमार की भूमिका महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच सहयोग भी विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो रहा है, जैसे पिछले वित्त वर्ष में भारत, म्यांमार के मुख्य व्यापारिक साझेदारों में से एक था। भारत ने म्यांमार को 820 मिलीयन डॉलर का निर्यात किया था और 540 मिलियन डॉलर का आयात किया था। दोनों देश निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा आदि में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। भारत ने म्यांमार में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण एवं परिचालन में भी म्यांमार को विशेष सहायता प्रदान की है। लेकिन दोनों राष्ट्रों के संबंधों में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे–रोहिंग्या समस्या, म्यांमार में चीन का बढता प्रभाव, पूर्वोतर राज्यों में म्यांमार से बढ़ती नशीले पदार्थों की तस्करी आदि। फिर भी रोहिंग्या समस्या का समाधान करके, परियोजनाओं में सुधार करके, बहुप्रतीक्षित मंचों पर सहयोग को बढ़ाकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

मुख्य शब्द :– एक्ट ईस्ट नीति, बिम्सटेक, कालादान, सिटवै।

शोधपत्र का उद्देश्य : इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत और म्यांमार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, रक्षा, आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों के स्वरूप को समझना रहा है, साथ में द्विपक्षीय संबंधों में मौजूद चुनौतियों एवं समाधान को भी समझने का प्रयास किया गया है।

शोध प्रविधि – शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक प्रद्धति का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीयक स्रोतों में लेखकों की पुस्तकों, शोधपत्रों, पत्रिकाओं एवं इण्टरनेट द्वारा अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना : भारत–म्यांमार के संबंधों की जड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और एतिहासिक जुड़ाव से जुड़ी हैं। दोनों राष्ट्रों के मध्य लगभग 1650 किमी, लंबी सांझी सरहद है। चार उत्तरी–पूर्वी राज्य अरूणाचल, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। म्यांमार में भारतीय मूल के लगभग 2.5 मिलियन नागरिक भी रहते हैं। भू– सामारिक कारकों से भारत और म्यांमार के लिए घनिष्ठ संबंध रखना महत्वपूर्ण है।

भारत म्यांमार संबंधों को दोनों देशों द्वारा अपनी सीमाओं पर शांति और सौहार्द्रता को बढावा देने, दीर्घकालिक आर्थिक विकास, आम नागरिकों के बीच आपसी मेल–मिलाप और उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में सांझे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने की सांझी इच्छा के रूप में देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे आदान–प्रदान में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई जिनके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय जुड़ाव में धनिष्ठता और व्यापकता आई है। यह व्यापकता विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिगत है, जो निम्नानुसार है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक सालो के दरम्यान दो बड़े तत्वों ने संबंधों को प्रभावित किया, जब वे दोनों नवोदित प्रजातंत्र थे। पहला तो दोनों प्रधानमंत्रियों जवाहर लाल नेहरू और यूनू के बीच प्रगाढ

मित्रता थी, जिसने घनिष्ठ परामर्श और निरन्तर यात्राओं के आदान–प्रदान में योगदान दिया। दूसरा एक अवरोधक तत्व म्यांमार में भारतीयों के साथ किया जाने वाला व्यवहार था, जिन्हें औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा विभिन्न क्षमताओं में लाया गया था और जिन्हें बर्मा के लोगों ने विदेशियों के रूप में देखा था। 1951 में दोनों देशों के बीच मैत्री संधि हुई जो एक दुष्प्राप्य गतिशीलता एवं लोच की प्रतीक थी। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने म्यामांर की यात्रा की तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दी। म्यामांर के राष्ट्रपति यूबिन सेन ने अक्टूबटर 2011 को भारत की यात्रा की तथा इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन ने भी 2012 में म्यांमार की यात्रा की जिस दौरान अनेक तथा करारों पर हस्ताक्षर किये गये। भारत ने म्यांमार को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लिए एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की। 2014 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने म्यांमार का दौरा किया साथ ही पड़ौसी पहले नीति को आगे बढ़ाया।

भारत के लिए म्यांमार का महत्व – म्यांमार भारत के लिए भू–राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत– दक्षिण पूर्व एशिया भू–भाग के केन्द्र में स्थित है। म्यांमार एकमात्र दक्षिण–पूर्व एशियाई देश है, जो भारत के साथ भूमि साझा करता है। म्यांमार एक ऐसा देश भी है जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति के केन्द्र में स्थित है। भारत के सागर विजन के अंग के रूप में भारत ने अमर के राज्य में सितवे बंदरगाह का विकास किया है। यह बन्दरगाह चीन–चित्र क्याउकप्यू बंदरगाह है जो चीन की भू–रणनीतिक स्थिति को बनाये रखने का उद्देश्य है जिसका मुकाबला कर सकने का भारत का प्रयास है। म्यांमार हमारी एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) और मेकांग गंगा सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। भारत–मयांमार के आर्थिक मूल्यांकन को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावों को महत्व देना महत्वपूर्ण है। भारत म्यांमार को शेष दक्षिण पूर्वी एशिया से जुड़ने का प्रवेश द्वार दिया गया है और इस प्रकार वह एशियाई भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने में सक्षम है।

म्यांमार ने भारत की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने सम्मान की पुष्टि की है और किसी भी विद्रोही समूह को भारत सरकार के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्य करने के लिए म्यांमार की धरती का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है। म्यांमार में भारत के प्राथमिक हित है– एक आर्थिक और सुरक्षा संबंध बनाना जो म्यांमार को चीन की कक्षा में जाने से रोक सके। पूर्वोत्तर उग्रवादियों के विशेष रुप से नागा विद्रोहियों को म्यांमार को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में उपयोग करने से रोकने में म्यांमार सेना का सहयोग सुनिश्चित करे। देश को पूर्ण संघीय लोकतंत्र में बदलने का समर्थन करें। रोहिग्याओं की दुर्दशा को सुधारना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच तनावपूर्ण संबंध नियंत्रण से बाहर न हो।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध– भारत सदियों से म्यांमार का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार रहा है। 1970 में भारत–म्यांमार व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से, द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है, हालांकि 80 के दशक में इसमें थोड़ी गिरावट आई थी। द्विपक्षीय व्यापार 1997–98 में 328 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2006–07 में 921 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, 2013–14 में 2.18 बिलीयन अमरीकी डॉलर, 2016–17 में 2.17 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 2017–18 में 1.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 2018–19 में द्विपक्षीय व्यापार में 7.53% की वृद्धि देखी गई है। जबकि म्यांमार से भारत के आयात में 18.47% की गिरावट देखी गई वही इसी अवधि के दौरान म्यांमार को भारत के निर्यात में 24.74% की वृद्धि देखी गई। भारत म्यांमार का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने म्यांमार के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए हवाई, भूमि और समुद्री मार्गों का विस्तार करने के लिए काम किया है। जबकि भारत के निजी क्षेत्र की भागीदारी कम रही है और धीमी गति से बढ़ रही है। दोनों सरकारे कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, इस्पात, तेल, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोकार्बन और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग बढाने के लिये आगे बढ़ रहे हैं। निवेश के मामले में नवम्बर 2019 तक 33 भारतीय उद्यमों द्वारा 771.488 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्वीकृत निवेश के साथ भारत 11 वें स्थान पर है। भारत में म्यांमार का निवेश 8.97 मिलियन अमारीकी डॉलर है। 13 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की म्यांमार में विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थिति है। भारत का अधिकांश निवेश तेल एवं गैस क्षेत्र में रहा है।

ऊर्जा सुरक्षा : ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसमें भारत की राज्य के स्वामित्व वाली और निजी कंपनियां उस देश में गैस ब्लॉक प्राप्त कर रही हैं। भारत को म्यांमार गैस के लिए ऑफ़ शोर हब बनाने, संचालित करने और उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। म्यांमार संभावित रूप से ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, क्योंकि भविष्य में अपतटीय गैस की खोज भारत में की जा सकती है। भारत के पास वर्तमान में तेल और गैस पर JWG और बिजली सहयोग पर JSC और JWG है।

खाद्य सुरक्षा– म्यांमार भारत को सेम और दालों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को म्यांमार से आयातित सामान में अन्य महत्वपूर्ण घटक लकड़ी व लकड़ी से बनी वस्तुएं है। इनके अलावा म्यांमार कृषि, वन, खनन, समुद्री, और पशु उत्पाद औद्योगिक तैयार उत्पाद और अन्य उत्पाद के सहयोगी और व्यापारिक सामान, कच्चा माल और व्यक्तिगत सामान का आयात करता है।

ऋण और बीमा – निवेश और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और एक्जिम बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय यांगून में है। मार्च 2016 में भारतीय स्टेट बैंक को वाणिज्यिक लाइसेंस से सम्मानित किया गया और व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरु की गई। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की म्यांमार में और अधिक वितीय सहायता प्रदान करना आसान बनाना आवश्यक है ताकि भारत में निवेश बढ़ाया जा सके। वर्तमान में कुछ भारतीय म्यांमार में निवेश के लिए सिंगापुर मार्ग का उपयोग कर रहे है, और उन्हें भारतीय निवेश के रूप में नहीं देखा जाता है। भारत और म्यांमार ने म्यांमार में जल्द से जल्द भारत का रूपे कार्ड शुरू किया और डिजीटल पेमेंट गेटवे के निर्माण का पता लगाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया।

म्यांमार में प्रमुख भारतीय परियोजनाएं :– भारत एक दर्जन से अधिक म्यांमार में सक्रियता से दोनों ढांचागत और गैर ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं में संलग्न है, जिनमें 162 किमी लंबी तामू –कलेवा– कलमयो सड़क पुनर्समतलीकरण और उच्चीकरण, रही– तिदिम और रही–फालम सड़कों का म्यांमार में निर्माण एवं उच्चीकरण, कालादान बहुमाध्यमीय परिवहन परियोजना इत्यादि। म्यांमार भारत अंग्रेजी भाषा केन्द्र, एक म्यांमार भारत उद्यमिता विकास केन्द्र और एक भारत–म्यांमार केन्द्र, आईटी कौशल विस्तार के लिए स्थापित किया गया है।

सांस्कृतिक संबंध– भारत और म्यांमार के बीच धनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। भगवान बुद्ध के जीवन के भारत के जुडाव को देखते हुए विशेष रूप से बौद्ध समुदाय में बंधुत्व की गहरी भावना मौजूद है। हम कुछ प्रमुख पहलुओं के माध्यम से इस सांझी विरासत का सर्वाधिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं : भारत सरकार बगान स्थित आनंद मंदिर के जीर्णोद्धार का काम कर रही है। भारत सरकार ने सारनाथ शैली की बुद्ध प्रतिमा की 16 फीट की एक प्रतिकृति दान में ही है, जिसे यंगून में शवे डैगन पगोड़ा के परिसरों में लगाया गया है। आई सी सी आर तथा सितागू अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अकादमी एवं म्यांमार के धार्मिक मामले मंत्रालय के समन्वय में विदेश मंत्रालय ने 15 से 17 दिसम्बर 2012 के दौरान बौद्ध सांस्कृतिक विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसके अलावा नियमित आधार पर भारत और म्यांमार की सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा परफार्मेंस को आयोजन किया गया। म्यांमार की मंडलियां एवं कलाकारों ने भारत दक्षिण एशिया तथा आसियान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लिया था।

रक्षा संबंध – भारत और म्यांमार पिछले कुछ वर्षों से अपनी रक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 200 से अधिक म्यांमार सैन्य अधिकारियों को भारत में चिकित्सा, वायुसेना और नौसेना क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। म्यांमार ने भारत से 37.9 मिलियन डॉलर कीमत के टॉरपीडो में लॉन्चर, नाइटविजन सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक्स और इंजीनियरिंग उपकरण शामिल है इत्यादि खरीदे है।

भारत और म्यांमार संबंध : चुनौतियाँ – भारत जमीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ होने की छवि से ग्रस्त है। नेपीडों में भारतीय दूतावास के संपर्क कार्यालय का उद्घाटन एक नियमित राजनयिक गतिविधि लग सकती है। हालांकि राजधानी में स्थायी : उपस्थिति स्थापित करना मायने रखता है। भारत सरकार देश में रोहिग्या प्रवासियों को लेकर चिंतित है। कहा जाता है कि लगभग 40000 रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। रोहिंग्या को म्यांमार भेजने पर बातचीत विवाद का मुद्दा है। भारत के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के बीच संतुलन बनाना रोंहिग्या मुद्दें पर उसके समग्र दृष्टिकोण की कुंजी में से एक है। आर्थिक सहयोग विकसित हुआ है, लेकिन यह अभी भी उप इष्टतम स्तर पर बना हुआ है। भारत का कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राखीन राज्य से होकर गुजरता है। प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो रही है। भारतीय सीमा पर बुनियादी ढांचे की कमी और व्यापार की कम मात्रा भी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सीमा पर हल्के हाथियारों, ड्रग्स और नकली मुद्राओं की तस्करी देखी गई है। बीजिंग सिटवें कुनमिंग मार्ग को बेहतर बनाने के लिए परियोजनाओ में निवेश कर रहा है। बेल्ट एंड रोड पहल की गति ओबामा की एशिया की धुरी की तरह भारत की एक्ट ईस्ट नीति को समाप्त कर सकती है। दोनों पक्ष एक लंबी समुद्री सीमा और भूमि सीमा सांझा करते हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चिंताएं पैदा हो गई है।

आगे बढ़ने का रास्ता : दोनों देशों को सुरक्षा और आतंकवाद निरोध, व्यापार और निवेश, बुनियादी ढाँचे और ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग को मजबूत करना चाहिए। म्यांमार की सेना के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। रोहिंग्या शरणार्थी मुद्दे पर कोफी अन्नान सलाहकार आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। भारत रखाइन राज्य में सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को सुधारने में मदद कर सकता है और रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है। दोनों देशों को माल और वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। एकल खिड़की मंजूरी और आसान मुद्रा व्यवस्था के साथ सीमा व्यापार को और अधिक औपचारिक बनाने की आवश्यकता है। सीमावर्ती हाट स्थानीय उपज के आदान–प्रदान को बढावा दे सकते हैं। सीमा पार बस सेवाएँ लोगों से लोगों के बीच कनेक्टीविटी को बढावा दे सकती है। चिकित्सा निदान, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सेवाओं में सीमा पर व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके लिए एक बड़ा बाजार

है। इन सबका मतलब होगा कि एक्ट ईस्ट नीति से पूर्वोत्तर को लाभ होगा।

निष्कर्ष : भारत और म्यांमार को भविष्य में सहयोग करने और अपनी शानदार सांझेदारी जारी रखने के लिए बहुत कुछ करना होगा। म्यांमार में भारत को अपनी विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से निष्पादित करने की गति तेज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत को यह समझने की जरूरत है कि ''चीन फैक्टर'' को म्यांमार सहित किसी भी देश के साथ उसके संबंधों को प्रभावित नहीं करना चाहिए और भारत को फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि नये सिरे से ध्यान दिया जायें तो भारत–म्यांमार संबंध एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं कि कैसे पडौसी महान मित्र और विकास भागीदार हो सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. एस. राज विवेकः भारतीय विदेश नीति, 2011–12, सिविल सर्विसेज टाइम्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली
2. एस.एन. ओझा : भारत एवं विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं
3. राजस्थान पत्रिका : संपादकीय अंक 8, सितम्बर 2019
4. द हिन्दू : संपादकीय अंक 31 अक्टूबर 2016
5. अनीक चटर्जी : नेबर्स, मेजर्स पावर्स एण्ड इण्डियन फॉरेन पॉलिसी
6. वेबसाइट : दृष्टि, ध्येय, अनअकेडमी, एमइए।